गुजरात में पहले चरण में 68 फीसदी वोटिंग पेज 18 | इशांत-जडेजा के

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2012, पटना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, विक्रम सम्वत, 2069 www.livehindustan.com

राज्य के शिक्षक अब नहीं करेंगे सर्वे

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

शिक्षकों को आंकड़ा जुटाने और सर्वेक्षण की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य में यह काम अब एक्रिडेटेड स्टैटिस्टिक्स वोलेंटियर्स (एएसवी) करेंगे। विभिन्न प्रकार के आंकड़े जुटाने और सर्वेक्षण के लिए इनकी सेवा अस्थाई रूप से ली जाएगी। आंकड़ा संग्रह में प्रखंड की बजाय पंचायत की प्रणाली अपनाने की वजह से सरकार ने यह प्रयोग किया है। फिलहाल एएसवी के माध्यम से फसल उत्पादन का ब्योरा जुटाया जाएगा। अगले वर्ष होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने तमाम राज्यों को एएसवी की तर्ज पर बहाली के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को योजना एवं विकास मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार एएसवी का प्रयोग हो रहा है। इसके लिए लगभग तीन लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से फिलहाल 25 हजार आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया। इनमें से लगभग 23 हजार को प्रशिक्षित किया गया। पिछले माह ली गई परीक्षा में 11079 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। हालांकि अगले वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण के मद्देनजर राज्य में कम से कम 80 हजार एएसवी की जरूरत होगी। विभागीय प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने बताया कि परीक्षा में सफल एएसवी को पंचायत आवंटित करके उनकी सूची जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को दे दी गई है।

जिम्मेदारी से मुक्ति

- खेत-खलिहान में घूमकर आंकड़ा जुटाएंगे एएसवी
- केन्द्र ने राज्यों को एएसवी मॉडल अपनाने को कहा
- एएसवी के लिए तीन लाख आवेदन मिले : मंत्री

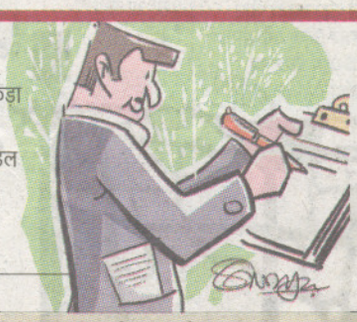

एएसवी के कार्य

- फसल क्षेत्र सर्वेक्षण और क्रॉप कटिंग
- सिंचाई सांख्यिकी का संकलन
- प्रक्षेत्र मूल्य का संग्रह
- पंचायतस्तर पर जन्म-मृत्यु निबंधन में सहयोग
- सकल घरेलू उत्पाद आकलन में सहयोग
- आर्थिक गणना व लघु सिंचाई गणना

अनट्रेंड शिक्षक बहाली की छूट दे केंद्र

पटना। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सेकेंड्री और हायर सेकेंड्री के शिक्षकों की नियुक्ति में 'प्रशिक्षित' होने की अनिवार्यता में एक बार के लिए छूट मांगी है। इसके साथ ही राज्य ने यह भरोसा दिलाया है कि यदि छूट मिलती है तो नियुक्त हुए अनट्रेंड शिक्षकों को तय समय सीमा में प्रशिक्षित कर लिया जाएगा।

राज्य के शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री पल्लम राजू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा संकट में है। राज्य के 30 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। श्री राजू को भेजे अपने पत्र में श्री शाही ने दो टूक कहा है कि बिहार को यदि यह छूट नहीं दी गई तो हजारों रिक्तियां यथावत रहेंगी और गंभीर परेशानी खड़ी होगी। बिहार ने सफलतापूर्वक शिक्षक पात्रता परीक्षा का संचालन किया जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पर इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बड़ी तादाद में पद रिक्त हैं। लेकिन हमारे पास इस गैप को भरने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों की भारी कमी है।श्री शाही ने साफ किया है कि पहले प्रशिक्षित अभ्यर्थी बहाल होंगे, उसके बाद अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों पर विचार होगा।